प्रसार भारती
आकाशवाणी शिमला

21.08.2025 / प्रादेशिक समाचार / 1945बजे

''मुख्य समाचार''

- मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा– प्रदेश के वित्तीय हालात सुधरते ही कर्मचारियों को लम्बित डीए जारी करेगी सरकार।
- कर्मचारियों के लम्बित डीए व एरियर को लेकर विधानसभा में हंगामा–विपक्ष ने सरकार पर वादाखिलाफी का लगाया आरोप।
- प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री व हिमाचल निर्माता डॉक्टर वाई.एस. परमार को भारत रत्न देने का प्रस्ताव विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित।
- ऑनलाईन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 संसद में पारित।

प्रश्नकाल

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश के कर्मचारियों को डी.ए. देना सरकार का कर्तव्य और दायित्व दोनों है। शिमला में चल रहे विधानसभा के मॉनसून सत्र में प्रश्नकाल के दौरान आज विधायक सतपाल सत्ती के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि तुरंत प्रभाव से इसे जारी किया जा सके ऐसे में वित्तीय हालात सुधरते ही लंबित डीए. जारी कर दिया जाएगा। इस पर विधायक बिक्रम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने मई माह में डी.ए. की किस्त देने की घोषणा की थी, जिस पर अमल नहीं हुआ है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट घोषणा के अनुसार डी.ए. दे दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ओ.पी.एस. देने के बाद केंद्र सरकार ने कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं और तीन वर्ष में कुल मिलाकर 4 हजार 8 सौ करोड़ रुपए कम मिला है, जिससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति को नुकसान हुआ है। इस पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस को सत्ता में लाने में कर्मचारियों का अहम योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को पूर्व भाजपा सरकार ने सारे लाभ दिए, लेकिन वे ओ.पी.एस. को लेकर नाराज थे। मुख्यमंत्री ने इस पर कहा कि पूर्व सरकार के समय का ही 11 फीसदी डी.ए. का भुगतान वर्तमान सरकार ने किया है।

उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने कर्मचारियों के लिए नए वेतन आयोग को लागू तो कर दिया, लेकिन 10 हजार करोड़ रुपए का एरियर नहीं दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के समय बढ़ी हुई आर. डी.जी. ग्रांट मिलने के बावजूद यह देनदारियां चुकता नहीं की गई। इस दौरान विपक्षी दल भाजपा ने सदन में नारेबाजी की और फिर वॉकआउट कर दिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधायक विनोद सुल्तानपुरी के प्रश्न के उत्तर में कहा कि राज्य सरकार विश्राम गृहों का किराया बढ़ाने पर विचार करेगी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विधायक मलेंद्र राजन के प्रश्न के उत्तर में बताया कि प्रदेश में एस.डी.एम. के माध्यम में समितियों का पंजीकरण किया जाएगा। विधायक कुलदीप सिंह राठौर के सवाल के जवाब में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि नवबहार स्थित बागवानी निदेशालय को शिमला से बाहर शिफ्ट नहीं किया जाएगा।

वॉकआउट

कर्मचारियों के लम्बित डीए व एरियर को लेकर आज विधानसभा में खूब हंगामा हुआ। प्रश्नकाल के दौरान विधायक सतपाल सत्ती के सवाल पर मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी सदस्य पहले वैल में नारेबाजी करते रहे और फिर सदन  से वॉकआउट कर दिया। बाद में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री सदन में बार–बार राजनीतिक जवाब दे रहे हैं और जिन कर्मचारियों की बदौलत कांग्रेस सरकार सत्ता में आई है उनसे किए वायदों को पूरा किया जाना चाहिए।

*अबकी बार बजट प्रस्तुत करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मई के महीने में डीए की किश्त जारी कर दी जाएगी, लेकिन मई बीत गया, जून बीत गया, जुलाई बीत गया और अगस्त जो है यह भी बीत गया, अभी तक वह डीए की किस्त कर्मचारियों को नहीं मिल पाई, कर्मचारी भाई बार–बार इस बात को लेकर के अपनी बात उठा रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि डीए की किश्त जो आपने कही थी वह तो जारी करो और अभी तक डीए की जो है 4+4+3 यानी कि 11 प्रतिशत देने को हो गई।*

दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष के वॉकआउट को राजनीति से प्रेरित बताया है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार आर्थिक चुनौतियों के बावजूद कर्मचारियों के हित में कई फैसले ले रही है और आर्थिक स्थिति ठीक होने पर कर्मचारियों की सभी देनदारियां दी जाएंगी।

*हमने बजट में जो अभी फैसला किया है कि आने वाले समय में सरकारी कर्मचारियों को जो हमने 3 प्रतिशत कहा है उसका डीए हम जरूर देंगे एनपीएस का जो पैसा पड़ा है केंद्र सरकार के पास 9000 करोड़ रूपये का उसमें 4500 करोड़ तो सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों का एनपीएस से जो पैसा कटता है वो है और जो 4500 करोड़ हमारा है कि हमें उसको मिलना चाहिए उस पर भी ये कुंडी डालकर बैठे हुए हैं किसी ना किसी तरह से प्रदेश के आर्थिक संसाधनों को भारतीय जनता पार्टी के कारण बंद किया जा रहा है अभी हमारा ध्यान सिर्फ ये है कि जो आपदा प्रभावित परिवार हैं, उनका मदद की जाए, उनको किसी तरह एस्टेब्लिश किया जाए, सड़कों को खोला जाए, उसके बाद हमारा दायित्व ये बनता है कि जो सरकारी कर्मचारियों की देनदारी है, उस देनदारी को हम धीरे–धीरे कम करेंगे और निश्चित रूप से जब बजट में मैंने घोषणा की है, बजट में उसका ऐलोकेशन किया है तो हम उनको डीए जरूर देंगें।*

संकल्प

विधानसभा में आज प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व हिमाचल निर्माता डॉ. वाई.एस. परमार को भारत रत्न देने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। पक्ष व विपक्ष के सभी सदस्यों ने विधायक अजय सोलंकी द्वारा सदन में लाये गए संकल्प पर राजनीति से ऊपर उठ कर परमार को भारत रत्न देने के लिए अपना समर्थन दिया। इस संकल्प पर दोनों पक्षों के विधायकों ने अपने विचार रखे। इसके जवाब में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि डॉ. वाईएस परमार को किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं वो जो इतिहास लिख गए हैं वो हमेशा रहेगा। पक्ष और विपक्ष का आभार जताते हुए उन्होंने कहा कि दलगत राजनीति से उपर उठकर सभी ने इस प्रस्ताव को पारित किया है। अग्निहोत्री ने कहा कि पहाड़ी राज्यों की स्थापना की बात होगी तो उनका नाम आएगा। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने भी विधायकों का आभार जताया और कहा कि सभी ने राजनीति से उपर उठकर अपनी बात रखने का प्रयास किया। संकल्प पर हुई चर्चा में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर, कैबिनेट मंत्री

हर्षवर्धन चौहान, जगत सिंह नेगी, रोहित ठाकुर, विधायक सुखराम चौधरी, हंसराज, विनोद सुल्तानपुरी, रीना कश्यप, नीरज नैयर और विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार ने भी हिस्सा लिया।

जीरो ऑवर

कृषि मंत्री चन्द्र कुमार ने कहा है कि प्रदेश के कई इलाकों में धान व मक्की की फसल खराब हो गई है और सरकार इस मामले में कृषि वैज्ञानियों द्वारा जांच करवा रही है। विधानसभा में आज शून्यकाल के दौरान विधायक केवल सिंह पठानिया द्वारा इस संबंध में उठाए गए मामले के दौरान उन्होंने ये बात कही। कृषि मंत्री ने कहा कि जो फसलें 30 प्रतिशत से ज्यादा खराब हो गई हैं। सरकार उन फसलों को रिलीफ मैनुअल में शामिल करने के लिए नियमों में संशोधन कर रही है। शून्य काल के दौरान विधायक आर.एस. बाली ने अपने सरकारी आवास के बिजली के भारी–भरकम बिल के मामले को सदन में उठाया। इस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस मामले की जांच करवाने की बात कही।

*बिजली बिलों के बारे में जब मेरे पास मन नहीं है विधायक रघुवीर सिंह वाली जी आए कि ये 14 महीने का बिल मेरा क्यों दिया गया? तो मैंने पूछा यह कैसे हुआ कहते जी की यह बिल पीडी वाले देते हैं मैंने अपना भी पता किया उन्होंने कहा कि यह आपका 140000 रुपए बनता है तो यह 14 महीने का बिल है। पिछला सरा एरियर इन्होंने जोड़कर दर्शा दिया कि हमने ये बिल इसको दिया है। तो इस मामले को सरकार ने बड़ी गंभीरता से लिया है। और मेरा मानना कि हम हर जगह स्मार्ट मीटर लगाएंगे। प्रीपेड मीटर भी लगाने जा रहे हैं।ताकि जब वो बिल पे करे तो उसको पता लगे जाए कि मैने कितने की बिजली कंजंप्शन की दिशा में आगे बढ़े हैं।*

इस बीच आर.एस. बाली ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस मामले की गहनता से जांच होनी चाहिए और ज्यादा बिल आने की वजह से उनकी छवि खराब हुई है।

*कि आंकड़े जो यहां पर रखे गए विधानसभा के अंदर वो गलत और 32 महीने का बिल जो था वो 298000 और मेरे से ऊपर जो मंत्री उनके बिल किसी के तीन लाख 45000 किसी का 346000 किसी का 393000 और किसी का ₹683000 इन 32 महीनों का बिल रहा। और मेरा बिल इन सब से नीचे पर जो आंकड़ा लाया गया और सोशल मीडिया में गया वह बहुत ही गंभीर विषय है कि किसने यह बात की। अगर यह जानबूझकर हुई क्योंकि विधानसभा में अगर आंकड़े दिए जाते हैं तो बहुत उसके ऊपर ऊपर से जिचे बहुत काम होता है उसके बाद दिए जाते हैं। तो यही बहुत बड़ी बात थी कि ऊपर से जिचे तक चेक होने चाहिए थे।*

विधेयक

संसद ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 पारित कर दिया है। केन्द्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस विधेयक से मध्यम वर्ग व युवाओं में बढ़ते ऑनलाईन मनी गेमिंग के नशे पर लगाम लगेगी।

'' मुख्य समाचार एक बार फिर''

- मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा– प्रदेश के वित्तीय हालात सुधरते ही कर्मचारियों को लम्बित डीए जारी करेगी सरकार।
- कर्मचारियों के लम्बित डीए व एरियर को लेकर विधानसभा में हंगामा–विपक्ष ने सरकार पर वादाखिलाफी का लगाया आरोप।

- प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री व हिमाचल निर्माता डॉक्टर वाई.एस. परमार को भारत रत्न देने का प्रस्ताव विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित।
- ऑनलाईन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 संसद में पारित।